स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीयकरण की मांग

जैसा कि कोरोना काल में पूर्णतः ज्ञात हो चुका है कि निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं, जो सामान्य काल में बहुसंख्यक ग़रीब वर्ग के लोगों के किसी काम की नहीं है, वही निजी सेवाएं स्वास्थ्य संकट के समय में अल्पसंख्यक अमीर वर्ग के लोगों के भी कुछ काम नहीं आ सकी, जो कि इन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सदैव भारी रकम चुकाते रहे हैं।

सरकारी अस्पताल, जो निजी करण के युग में उपेक्षित किए गए थे, वही हम भारतवासियों के बचाव में सामने आए।

तालाबंदी के पहले 80% मरीज़ निजी स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ जाते थे क्योंकि निजीकरण के युग में सरकारों ने, सरकारी अस्पतालों के निधि करण (फंडिंग) की उपेक्षा करी थी।। ऐसे मामले सामने आए थे जहां प्रतिष्ठित सरकारी अस्पताल, जिनके साथ मेडिकल कॉलेज भी जुड़े थे, उनके पास सही इसीजी मशीनें भी नहीं थी। मरीजों को नियमित रूप से मेडिकल टेस्ट और दवाइयां बाहर से लेने की सलाह दी जाती है। चाहे उपकरण हों या कर्मचारी हों या दवाइयां हों, सरकारी अस्पतालों में इनकी हमेशा कमी रही है।

सामान्य समय में भी निजी चिकित्सक भारी भरकम फीस लेते रहे हैं और बड़े पैमाने पर होने वाली अनावश्यक जांच, दवाईयां और शल्य क्रियाओं के गोरखधंधे की बात किसी से छिपी नहीं है। हमें बीच-बीच में ऐसी खबरें मिलती रहती है और हम इन्हें टोकरी के ख़राब सेब का लेबल दे देते हैं। पांच सितारा कॉरपोरेट अस्पतालों से लेकर छोटे निजी अस्पतालों में मरीज आर्थिक रूप से और स्वास्थ्य सेवा के मामले में पीड़ित होते रहते हैं।

लेकिन कोरोना ने पूरी प्रणाली को पूर्ण रूप से उजागर कर दिया है। तालाबंदी की घोषणा होते ही निजी अस्पतालों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। यहां तक कि उन्होंने गैरकोरोना रोगियों को भी देखना या भर्ती करना बंद कर दिया। एंबुलेंस सेवा जो कि अधिकांश शहरों में निजी हाथों में है, सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा 10 गुना अधिक एम्बुलेंस निजी है, उसने भी काम करना बंद कर दिया। जब सरकार के द्वारा निजी अस्पतालों को कोविड-19 रोगियों के लिए खोलने के लिए मजबूर किया गया, तो हम सब जानते हैं कि उन्होंने कितना भारी शुल्क लिया, ऐसे मामले ज्ञात हुए जिसमें कोविड रोगियों की चिकित्सा मोलभाव के बाद, भारी शुल्क लेकर की गई। अतः पैसों का लालच किसी अन्य व्यवसाय की तरह ही उजागर हुआ।

इन कारणों से सरकारी अस्पतालों पर अतिरिक्त भार आ गया और उन्हें कोरोना के हल्के लक्षणों वाले और यहां तक कि जिनको कोई लक्षण नहीं था सिर्फ टेस्ट पॉजिटिव था ऐसे लोगों को भी भर्ती करना पड़ा। जो भी मरीज पहले शहर में अलग-अलग जगहों पर मर रहे

थे अब सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही मर रहे थे। शवदाह ग्रहों की अतिरिक्त प्रक्रियाओं के कारण हमने शवों के ढ़ेर लगते हुए देखे।

हमें यह मानना होगा कि इन सब के बावजूद मुख्य रूप से स्वतंत्रता के बाद से 90 के दशक तक स्थापित की गई सरकारी सुविधाएं संकट के इस समय में रीढ़ की हड्डी साबित हुई।

इससे हम भारत वासियों ने यह सीखा है कि स्वास्थ्य हमारे जीवन का ऐसा अति संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जिसे हम समानांतर चलने वाले निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच उपेक्षित नहीं कर सकते। हमने देखा है कि इन परिस्थितियों में अनेक कारणों वश सार्वजनिक क्षेत्र की उपेक्षा होती है और निजी क्षेत्र और ज्यादा वाणिज्यिक/पैसा केंद्रित हो जाता है। अंततः जनहित का निर्वाहन नहीं हो पाता।

दवाई की कंपनियां स्वास्थ्य व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। दवाइयां किफायती दाम से मिले वह तो जरूरी है ही, मगर दवाई के खोज, अनुसंधान, परीक्षण, भी लोगों की जरूरत के मुताबिक होने चाहिए। इसके कई उदाहरण है जैसे कि बीसीजी वैक्सीन एक बार सरकार के सार्वत्रिक प्रोग्राम में दाखिल कर लेने के बाद उसकी असर का कोई मूल्यांकन नहीं हो रहा, उसे और अच्छा बनाने की जरूरत है कि नहीं, वही नहीं देखा जा रहा। टीके के बाद भी लोगों को टीबी तो हो रहा है, आज भी हमारे देश में रोज के करीब 1400 लोग टीबी से मर रहे हैं।

पोलियो के लिए पिलाये जा रहे वैक्सीन से भी बच्चों को नुकसान हो रहा है वह पता होने के बाद भी उस को बदलने की शुरुआत बहुत देर से की जा रही है। इंजेक्शन वाला पोलियो वैक्सीन ज्यादा सुरक्षित है वह पहले से पता था, फिर भी पैसे बचाने के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन शुरू किया गया।
इसलिए जब हम स्वास्थ्य सेवा के राष्ट्रीयकरण की मांग करते हैं तो उसमें दवाई की कंपनियों का भी राष्ट्रीयकरण करने की मांग कर रहे हैं। उसी से जरूरत के मुताबिक, अनुकूलतम उत्पादन करके सबको जरूरत पड़ने पर दवाई मिले यह कर सकते हैं।

हमें एक मजबूत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसमें देश के सभी संसाधनों को लोगों की उत्तम सेवा के लिए उपयोग में लाया जा सके। बेशक सरकार को अधिक खर्च करना होगा और इसके लिए सरकार को अमीर वर्ग पर ज्यादा कर/टैक्स लगाना होगा। सालों से उन्हें सभी तरह के कर लाभ, रियायतें, कर मुक्त अवधि, कर कटौती, बेलआउट और अन्य कई लाभ दिए गए हैं। सुपर रिच टैक्स एक ऐसा उपाय है, वेल्थ टैक्स और इन्हेरिटेंस टैक्स भी लगा सकते हैं। वैसे भी टैक्स का स्लैब बहुत अमीर लोगों के लिए बहुत कम है।

सरकार जो भी योजनाएं लाती है, जैसे कि आयुष, या बीमा कंपनियां स्वास्थ्य के लिए जो बीमा हमें देते हैं उसमें गरीबों का पैसा अंत में अमीरों की दवाई में और अमीर डॉक्टरों और अमीर हॉस्पिटलों की जेब में जाते हैं। इस देश की नागरिकता ही मेरा बीमा है। कोई बीमा या उसका प्रीमियम नहीं। सबको अच्छी और मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा मिले ऐसी व्यवस्था खड़ी की जा सकती है।

लोगों का स्वास्थ्य, जिंदगी, कुछ लोगों की अति शानदार जीवन शैली से अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा अनुभव है कि विश्व में जहां भी स्वास्थ्य सेवाओं का अच्छी तरह से राष्ट्रीयकरण किया गया है, वहां अनावश्यक जांच, दवाइयां और शल्य क्रियाओं से बचा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर वह सदैव उपलब्ध रहती है।

उसके लिए हम निम्नलिखित मांग करते हैं:

- संपत्ति के मूल्यांकन पर उचित मुआवज़े के साथ निजी क्षेत्रों के अस्पतालों का तत्काल अधिग्रहण। छोटे अस्पतालों को सरकारी मोहल्ला अस्पतालों में बदला जा सकता है।
- गांवों के उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर ज़िला स्तर के अस्पतालों और मल्टीस्पेशलिटी अस्पतालों की पहले से जो मौजूद सरकारी व्यवस्था है, उस श्रृंखला को मजबूत और विस्तृत करना।
- हर स्तर पर पर्याप्त चिकित्सकों, नर्सों और अन्य पैरामेडिकल कर्मचारियों को उपलब्ध कराना चाहिए। सभी चिकित्सकों का पोस्ट ग्रेजुएशन से पहले और बाद में ग्रामीण स्तर पर सेवा का अनिवार्य होना और जरूरत के हिसाब से उनका आवर्तन/रोटेशन होना लागू करो।
- सभी चिकित्सकों और अन्य मेडिकल कर्मचारियों को एक अच्छा गरिमामय वेतन दिया जाए और आई ए एस अफसरों की तरह उनके अनुभव और अतिरिक्त शिक्षा के आधार पर उनकी पदोन्नति की जाए।
- सबसे महत्वपूर्ण बात यह है की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था का कामकाज लोगों के सीधे लोकतांत्रिक नियंत्रण से चले वह कायम करना है।
- अस्पताल प्रशासन के लिए डॉक्टरों के प्रतिनिधि, अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के प्रतिनिधि और इसी काम के लिए चुने गए जनप्रतिनिधियों की एक समिति बनाई जाए। यह समिति दिन प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने के लिए काम करें।
- शिकायत और सुझाव बॉक्स के अलावा लोगों की शिकायतें होती है, उनको सुनने के लिए अस्पताल हर महीने एक सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन करें। इन मीटिंग में ही सुझाव बॉक्स खोले जाने चाहिए।
- हर बार अस्पताल आने पर प्रत्येक मरीज़ को एक सर्वेक्षण प्रपत्र/फॉर्म, जो कर सके उनके लिए डिजिटल, देना चाहिए, जिसमें वह अपने अनुभव बता सकें, जैसे कई बैंक एवं अन्य कंपनियां अपने काम को बेहतर बनाने के लिए कर रही हैं।

- एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव यह भी है की चिकित्सा के विभिन्न तरीके जैसे एलोपैथी, होमियोपैथी, आयुर्वेद और अन्य पद्धतियों को भी सभी छात्रों को स्नातक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए और केवल इनकी विशेषज्ञता सर के लिए अलग-अलग प्रशिक्षण लें। इस तरह सबसे अच्छा तरीक़ा मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पारस्परिक अलग अलग होने के बजाय यह तरीके एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। आज तो मरीज़, जिसे कम जानकारी है वह निर्णय लेता है कि इस बीमारी के लिए कौन सा तरीका चुनना चाहिए।
- पर्यावरण विज्ञान और उससे जुड़े रोग पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहिए।
- दवाई की कंपनियों का राष्ट्रीयकरण होने के बाद उसके सभी निर्णय पारदर्शी तरीके से लिए जाएंगे। उसके प्रशासन के लिए सार्वजनिक रूप से हो रही चर्चाओं के माध्यम से जनता को जिस में विश्वास होगा, उन प्रतिनिधियों को रखा जाये।

लोगों का सरकार पर यह सब करने के लिए दबाव डालना और लोगों की जिंदगी को गंभीरता से लेने की एक विस्तृत प्रसार मांग ही सुरक्षित भविष्य का एकमात्र तरीका है।

-डॉक्टर माया वलेचा
Mobile No. +917016002688 Email: maya11156@gmail.com